

सम्पादकीय

ટ્રાઇબ્યુનલ પર ટકરાવ

अदालत को हैरानी इस बात पर थी कि बार-बार कहने और मौजूदा कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन करते हुए नाम भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्राइब्यूनल में खाली पड़े पदों को भरने में हो रही देरी को लेकर असाधारण सखी दिखाई है। उसने कहा है कि लगता है कि जैसे सरकार के मन में इस कोर्ट के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह हमारे शैर्य की परीक्षा ले रही है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर नियुक्तियां करने को कहा। अदालत को हैरानी इस बात पर थी कि बार-बार कहने और मौजूदा कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन करते हुए नाम भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। सरकार की ओर से इसका कोई ढंग का स्पष्टीकरण भी पेश नहीं किया जा सका कि आखिर नियुक्तियां न किए जाने की क्या वजह है रही। लेकिन मामला सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं। अदालत की नाराजगी सरकार की ओर से पिछले महीने लाए गए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर भी है। इससे मिलते-जुलते प्रावधानों वाले पिछले कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। इसके बावजूद वैसा ही प्रावधान नए कानून की शाकल में लाए गए। शीर्ष अदालत ने इस पर तीखी आपत्ति करते हुए कहा कि हम किसी कानून के खिलाफ फैसला देते हैं, आप कुछ दिनों बाद वैसा ही नया कानून ले आते हैं। यह एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे ऐसा संदेश जासकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं करती।

अदालत ने जिम्मेदारी और अधिकारों की बारीक सीमा को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार फैसले का मुख्य संदेश ग्रहण करते हुए उसके अनुरूप नया कानून बना सकती है, वह किसी फैसले के आधार को भी बदल सकती है, लेकिन फैसले की मुखालफत करते हुए कोई नया कानून नहीं बना सकती। फैसले का आधार बदलने और मुखालफत करने के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए अंतर पर थोड़ा गैर किया जाए तो साफ होता है कि सरकार किसी खास कानून में संशोधन करके कोर्ट द्वारा की गई उसकी पिछली व्याख्या के आधार को और विस्तृत कर सकती है, जिससे हो सकता है अगली बार कानून की वह व्याख्या बदल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के जिस प्रावधान को खारिज करे, वही प्रावधान फिर से लाए जाएं तो यह कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो जाता है। इसे ठीक नहीं माना जा सकता। वैसे यह भी सच है कि अभी इस मामले की सुनवाई चल ही रही है और केंद्र सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जाना बाकी है। अभी यह मानना मुनासिब होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गंभीरता को समझती है। लेकिन किसी भी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में उसके आदेशों की अनदेखी हुई है तो सरकार को इस मामले की तहतक जाते हुए उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और उन्हें अविलंब दूर करना चाहिए।

चलो, एक न्यायपरक और समतामूलक समाज की ओर चलें

डॉ. सुधा कुमारी

प्रकृति ने इस धरती पर सब तरह के जीव-जन्तु बनाए हैं। सबकेवें लिए धूप-हवा-पानी और भोजन की व्यवस्था की है। सभी जीवों में प्राण और शरीर की व्यवस्था की है। सभी जीवों के अंदर मूल भावनाएँ भी दी हैं, जैसे-भूख-प्यास, जीने की इच्छा, प्रेम। मानव प्रजाति को तो प्रकृति ने एक उत्तर और उर्वर मस्तिष्क भी दिया है जिससे वह कई महान कार्य करता है। फिर भी यह विश्व सुखी और शांत क्यों नहीं है? दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मानव प्रजाति के पास शांति क्यों नहीं है? कभी देशों और महादेशों के बीच युद्ध, कभी सरकार और जनता वें बीच टकराव, कभी उच्च वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग का शोषण, कभी निम्न आय वर्ग द्वारा उच्च वर्ग के साथ लूटपाट, पॉकेटमारी और सामाजिक अपराध, कभी पुरुष वर्ग द्वारा स्त्री का शोषण और अपराध और कर्भं स्त्री द्वारा पुरुष पर अत्याचार- आखिर इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है? इस पर शोध करने की आवश्यकता है और प्रबुद्ध लोगों द्वारा काफी मनन चिंतन की आवश्यकता है। जब तक पूरे समाज का संतुलित विकास नहीं होगा, उसके सभी अंगों और वर्गों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, जब तक अलग-अलग हिस्सों में धूप-छाँक का खेल चलता रहेगा, तब तक समाज और विश्व में संघर्ष चलता रहेगा। इसलिए तरह-तरह की असमानताएँ या विषमताएँ और असंतुलन जो विश्व के हास्त हिस्से में फैली हुई हैं, उसे न्यूनतम करना होगा। असंतुलित और असमान समाज से निकलकर एक न्याय परक और समात मूलक समाज की ओर बढ़ना होगा। जीवन-प्रवृत्ति (लाइफ इन्स्टिंक्ट) एक सामान्य और मौलिक प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत, सामान्य प्रवृत्तियाँ जैसे भूख-प्यास, जीने की इच्छा, नींद, बच्चों से प्रेम, साथी से प्रेम, अपने झुड़के प्रति वफादारी और सुरक्षा की आवश्यकता- सभी जीवों में होती हैं। किन्तु एक अन्य मौलिक प्रवृत्ति भी है जो करीब-करीब सभी प्रजातियों में पाई जाती है जिसे मनोविज्ञान मृत्यु-प्रवृत्ति (डेथ इन्स्टिंक्ट) के नाम से पुकारता है। जहाँ जीवन-प्रवृत्ति (लाइफ इन्स्टिंक्ट) जीवों को प्रेम, विकास और वंश वृद्धि की ओर उन्मुख करती है, वहीं मृत्यु-प्रवृत्ति जीवों को क्रोध, हिंसा और विधंस की ओर उन्मुख करती है। इस प्रवृत्ति के कारण हिंसा, अपराध और युद्ध का उन्माद देखने को मिलते हैं। मौलिक (बैसिक) प्रवृत्ति होने के कारण ये भावनाएँ पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकतीं किन्तु उसपर नियंत्रण बहुत आवश्यक है और इसकी शिक्षा बचपन से ही मिलनी चाहिए 'आहेसा परमोदर्थम्' ऐसी धारणा सिर्फ भारत की है, पूरे विश्व की नहीं और भारत में भी यह धारणा हर किसी व्यक्ति की नहीं है। यदि ऐसा होता तो पूरा देश संत-मुनियों से भरा होता। जीव-हत्या, बलप्रथा मारपीट, शारीरिक अत्याचार-इन सभी के कारण और उद्देश्य अलग हैं, जैसे भोजन के कारण जीवहत्या होती है, किसी अदृश्य शत्तिया या देवता को प्रसन्न करने के कारण बलि होती है, झगड़े या विवाद वें कारण मारपीट और मानसिक रुग्णता के कारण शारीरिक अत्याचार होता है। किन्तु कारण अलग-अलग होने के बावजूद उसका प्रभाव एक जैसा होता है क्योंकि इन सभी क्रियाओं से जीव की घातक चोट लगती है और वह दर्द से तड़पता है।

है। किन्तु युद्ध का उन्माद और वातावरण पैदा करना कुछ लोगों की कार्ययोजना होता है, सोची-समझी साजिश होती है। कोई देश अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिये अधिक जमीन हड्डपना चाहता है और अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाना चाहता है तो कोई अपने अस्त्र शस्त्र के कारोबार के

जीवित रखने की गरज से युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहता है। कोइस पक्ष या उस पक्ष का साथ देने की गरज से ही युद्ध और हिंसा की भावना फैलता है। पर सभी के कारण अलग होने पर भी उसका प्रभाव एक-सा पड़ता है- सैनिक एक दूसरे पक्ष पर आक्रमण करते हैं, घातक वार किए जाते हैं, कितने लोगों की जान जाती है, परिवार उज़इ जाते हैं। रक्त की लोहित नदियों बहती हैं, औंसुओं के खारे सागर बनते हैं। क्या सभी विवादों का हल युद्ध है? बातचीत, आपसी सहयोग, सदभाव रिवाज, विवाद हल नहीं हो सकते? कूटनीति, समझौते, व्यापार-विनियम क्या उसमें सभी व्यर्थ हो चुके हैं? उत्तर है, नहीं। मनुष्य का मन, भावनाएँ, प्रतिक्रियाएँ जरूरतें- अन्य सभी जीवों से अधिक उच्चत और जटिल बनाई गई हैं। इसके कई सारे सुपरिणाम हैं कि मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, बड़े-बड़े अनुसंधान करता है, सागर के तल और आकाश-अंतरिक्ष के पार पहुँचता है, कोनिरंतर प्रयासरत रहता है। धन जमा कर उसका विनिवेश करता है, बड़े-बड़े उद्योग-कारखाने चलाता है।

मनुष्य कला-शिल्प में नई-नई दिशाएं हूदूता है, मनोरंजन और सुविधा के लिये तरह-तरह के यंत्र और साधन बनाता है। दीन-दुखी की सहायत के लिए दान-कोष, ट्रस्ट और समितियाँ बनाता है, सामाजिक जीवन अनुशासन के लिये एक संविधान, नियम-कानून बनाने के लिए संसद उनके कार्यान्वयन के लिए कार्यपालिका और उन नियमों की अवमानन करनेवालों को दण्डित करने के लिए न्यायपालिका भी बनाता है। इतन ही नहीं, मनुष्य तपस्या और योग साधना कर ईश्वरत को भी प्राप्त करता है। मनुष्य जैसे विकसित प्राणी को प्रकृति ने अद्भुत इच्छात्मिक और चिंतनशक्ति दी है। उसे ज़ंगली जीव-जंतुओं की तरह उग्र, आक्रामक और हिंसक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। युद्ध के अलावा बहुत राशनीपूर्ण उपाय हो सकते हैं जैसे- आर्थिक- सामाजिक- सांस्कृतिक सम्बन्ध का विकास, हिंसा की जगह मित्रता को बढ़ावा देना। इसके प्रकार, हिंसक अपराध करने का कारण कभी गरीबी है और कभी मानसिक रुणता या बीमारी। गरीबी के कारण नौकर मालिक की हत्या कर धन प्राप्त करता है, अशिक्षा या तनाव या अवसाद या कुंठा देकारण विवाह-संबंधी अपराध होते हैं। यदि विवाह के पूर्व स्त्री-पुरुष का उचित परामर्श तथा मेडिकल सहायता और परामर्श दिये जायें तो उनके उचित दिशा-निर्देश हो सकता है और विवाह के बाद भी दिशा-निर्देश या परामर्श नियमित मिलता रहे तो मानसिक बीमारियाँ, तनाव या कुंठा आदि व्याधियों से विवाहित जोड़ों को बचाया जा सकता है। ध्यान रखें तो पाएंगे कि सभी अपराधों के गीछे अशिक्षा, तनाव, दिशाहीनता या बेरोजगारी मूल्य कारण होते हैं। यहाँ प्रसिद्ध रूसी लेखक दोस्तोएस्क्स की पुस्तक 'क्राइम एंड पनिशमेंट' का उल्लेख अति आवश्यक है जिसमें एक धनी व्यक्ति के गरीब हत्यारे के गंदे और अँधेरे कमरे का जिक्र करता हुए कहते हैं कि अँधेरे, सीलन भरे और नीची छत वाले घर में रहनेवाले व्यक्ति अपराध के बारे में ही सोच सकता हैं। कितना हृदय-विदारक और सत्य कथन है ! निर्धनता को दूर करना अति आवश्यक है, उच्चर्वा भी तभी चैन से रह सकता है।

अपराध कम करने के लिये युवाओं का आह्वान आवश्यक है। यदि जयप्रकाश नारायण डाकुओं को परिवर्तित कर सामान्य धारा में ला सकते तो जयप्रकाश नारायण के परम अनुयायी और समर्थक अन्य छोटे-मोटे चोर-उचकों और गुंडे-बदमाशों को क्यों नहीं सुधार सकते? उन्हें सामान्य धारा में आकर रोजगार चाहिये। तभी वे अपराध के ज़ंगल से बाहर आएंगे। अपराध कोई शौक नहीं है क्योंकि इसमें जान का खतरा और कानून का डर होता है। यदि रोजगार-व्यवसाय की व्यवस्था हो तो लोग व्यस्त रहेंगे। उनके पास फालतू वक्त नहीं रहेगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए

उद्योग-धन्धे, कला-शिल्प, कृषि-संबंधी रोजगार और स्व-रोजगार का प्रयास करना आवश्यक है। सबको शिक्षा मिले, इसके लिये विद्यालय के साथ-साथ अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा दी जानी चाहिए। गाँव में अनौपचारिक रूप से कुछ जगहों की व्यवस्था कर उन लोगों को शिक्षा दी जा सकती है जो विद्यालय आने में असमर्थ हैं या विद्यालय में उन्होंने समय नहीं दे सकते। उन्हें किताब-कॉर्पियाँ और कलम दिये जा सकते हैं जिससे घर में रहकर भी बड़े-बूढ़े, गृहिणी-बच्चे सीख सकें। प्रतिदिन दो घंटे भी यदि उन्हें शिक्षा मिले तो उनका मानसिक धरातल ऊँचा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनमें जागरूकता आएगी। फिर अनौपचारिक रूप से आय अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाय। यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलें। महिलाओं के साथ अपराध को रोकने के लिए उन्हें आत्मनिर्भरता की शिक्षा और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उन्हें अपने घर से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिये संपत्ति मिलना जरूरी है। साथ ही, अपने माता-पिता की देखभाल भी करनी है। उन्हें घर में रहकर या बाहर जाकर रोजगार या उद्योग में भाग लेना है। यदि विश्व की जनसंख्या का 50% हिस्सा लाचार, असमर्थ या आलसी बनाकर घर में बैंद कर दिया जाय तो पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे आएगी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे बढ़ेगा? क्या घर में बैठकर झाड़ लगाने से सकल उत्पाद या जी.डी.पी. बढ़ सकती है? आर्थिक अधिकार तो महिला को अपने घर से मिलना चाहिए और आत्मनिर्भरता भी वहीं से आरंभ होनी चाहिए, शिक्षा और आर्थिक साधनों से आरंभ होनी चाहिए। इससे उसे स्वतः गरिमा और सम्मान प्राप्त होंगे। निर्धन, परतंत्र और अशिक्षित महिला को सम्मान और अधिकार माँगना पड़ता है जो अवसर नहीं मिलता। अतः उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता और संपन्नता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इसमें पूरे परिवार और समाज की भलाई है। 3000 साल पुरानी महिला विरोधी कट्टर रुद्धियों से समाज की गाड़ी के पहिए पुनः असंतुलित हो जाएंगे। कोई भी गाड़ी तभी चल सकती है जब उसके सभी पहिये समान शक्ति के हों। उसके प्रेम, विवाह या वैवाहिक स्थिति पर कोई चर्चा, प्रश्न या विवाद नहीं खड़ा करे। समाज पूरी शांति से चले, पुरुष-महिला दोनों को समान भाव से कार्य करने दे। हर दस्तावेज में पिता, पति या अभिभावक का नाम लिखना और इसके लिये उसे कानून द्वारा बाध्य करना महिला का सरासर अपमान है। क्या वह असमर्थ या लाचार है? विशेष रूप से जब बायोमेट्रिक्स द्वारा हर व्यक्ति की जैविक पहचान सुनिश्चित है तो उसमें पिता, पति या अभिभावक का नाम क्यों दिया जाय? फिर आँख और उंगलियों के फोटो से क्या लाभ? यदि पति-पिता-पुत्र का नाम लिखना अनिवार्य ही है तो बायोमेट्रिक्स क्यों लगाया? यदि वंशानुगत पहचान आवश्यक है तो माता-पिता दोनों क्यों नहीं हो सकते? आज की गंभीर परिस्थिति में हमें एक न्यायपरक समाज की बेहद आवश्यकता है। नकारात्मक शक्तियाँ- कट्टरता, पोंगांपंथी, ढकोसला, अशिक्षा, प्रतिक्रियावादी ताकतें चारों और से देश को निगलने को आतुर हैं, बस मौके की तलाश है। इनसे बचने के लिए एक न्यायपरक, शांतिपूर्ण, समानतापूर्लक समाज की स्थापना हमारा परम लक्ष्य है। ऐसा समाज सबका आदर करता है, सबको अनुशासित रखता है और सबको आगे बढ़ने का अवसर देता है। समानतापूर्लक समाज में सबके लिये स्थान है, सहयोग है, विद्रोष या शुरुता नहीं है। शिक्षा और आर्थिक विकास जनसंख्या को संतुलित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य में एक प्रवृत्ति है जो अन्य जीवों में नहीं है। इसे मनोविज्ञान 'नीड फॉर अचीवर्मेंट' के नाम से पुकारता है। इसे महत्वाकांक्षा की भावना भी कह सकते हैं। इसी भावना ने उसे अंतरिक्ष के पार जाने का साहस दिया, समुद्र की तलहटी खंगालने का बल दिया। यिन्होंने की सृष्टि करवाई, नए-नए अनुसंधान करवाए। यदि वह चाहे तो ऐसा समाज अवश्य स्थापित होगा जहाँ हर प्रकार के लोग मिलकर रहें।

नीतीश कुमार हैं पीएम मटीरियल!

जयशकर गुप्त

राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार अभी तक इन दबावों को झेलते और भरसक परे करते रहते हैं। भाजपा के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी राय भाजपा से अलग है। इसी तरह से पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच कराए जाने की विपक्ष की मांग का समर्थन कर उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर एक तरह का दबाव ही बनाया। उन्होंने जातीय जनगणना पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर इसके लिए उन पर दबाव भी बनाया।

इन दिनों बिहार की राजनीति में पीएम यानी प्रधानमंत्री मटीरियल की चर्चा बहुत जौरों पर है। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बनें रहने का रिकार्ड बनाने वाले नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोग एक अरसे से पीएम मटीरियल मानते और बताते रहे हैं लेकिन इस बार जब 29 अगस्त को जनता दल ;यूद्ध की राष्ट्रीय परिषद ने इस आशय का एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास कर दिया तो बात में गंभीरता नड़ा आने लगी है। यह बात और है कि अभी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नजर नहीं आ रही है।

जाहारा तर पर नातोश कुमार न यहां कहा है कि वह इन बातों पर ध्यान नहीं देते। पार्टी में लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में इस तरह का राजनीतिक प्रस्ताव कैसे पास हो गया! ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना यह प्रस्ताव तेयर और पास भी हो गया हो! लोकसभा के चुनाव पैने तीन साल बाद होने हैं और अभी वह जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन; राजगढ़ में शामिल हैं ए उसमें प्रधानमंत्री का पद और भविष्य की दावेदारी भी खाली नहीं है। उनके समर्थक और उन्हें प्रधानमंत्री पद के काबिल बताने वाले उनकी पार्टी के नेता क्या यह सोचते हैं कि 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी भाजपा में उम्र के पैमाने के महेनजर प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं रहेंगे और भाजपानीतेराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित राजग बिहार की बादशाहत की तरह ही लोकसभा में 15.20 सांसद की राजनीतिक ताकत वाले नीतीश कुमार को नेतृत्व की दावेदारी सौंप देंगा! फिलहाल तो यह द्विवास्त्रज से अधिक कुछ और नहीं

लगता। इसके लिए दूसरा विकल्प 2024 में संयुक्त विपक्ष उन्हें अपना वैकल्पिक चेहरा मानकर चुनाव लड़े। तो क्या उनकी निगाह एक बार फिर से पलटी मार कर नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोध में बनने वाले किसी संभावित राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व करने की ओर लगी है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटीरियल बताने के पीछे उनकी और उनके जद ;यूद्ध की राष्ट्रीय पहचान बनाने की कवायद भी हो सकती है। जद ;यूद्ध नेताओं की कोशिश उत्तर प्रदेश और मणिपुर विधानसभा के चुनाव में भी अगर भाजपा से बात बन जाती है तो उसके साथ मिलकर और सम्पानजनक सीटें नहीं मिलने पर अपने बूते भी तकरीबन आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की लगती है। अगले साल ही जम्मू. कश्मीर और गुजरात विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जद ;यूद्ध की कोशिश इन राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कुछ सीटें और अपेक्षित मत प्रतिशत हासिल कर चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल करने की हो सकती है। राष्ट्रीय अद्यक्ष बनने के बाद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कश्मीर यात्रा कर वहां भी पार्टी के पांच पसराने

नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मटीरियल वाली राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इससे पहले भी कई बार हिलोर मार चुकी हैं। 2014 के संसदीय चुनाव के समय भाजपा की तरफ से नरेंद्र मौदी को प्रधानमंत्री पद के दावादार के रूप में पेश किए जाने के विरोध में उनकी पार्टी ने

आ सक्री। नीतीश कुमार के लिए यह एक राजनीतिक झटका था हालांकि वादे के मुताबिक भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हैं साझा सरकार बनवाई लेकिन क्रमशः इसकी कीमत भी वसूल लगी। उन्हें इस बात का एहसास भी कराया जाने लगा है कि वर्षभाजपा के रहमोकरम पर ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार ट्रैसामने एक बार फिर 2015 के बाद वाली ही स्थिति उभरकर सामने आने लगी है। पिछले सप्ताह बिहार के छपरा में जेपी विश्वविद्यालय गुपचुप ढंग से भाजपा का एजेंडा लागू करने की साजिश उत्तराखण्ड वहां राजनीति शास्त्र के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वतीए राजा राममोहन रायए लोकमान्य तिलक और नीतीश कुमार के राजनीतिक आराध्य और आदर्श रहे समाजवादी नेता डॉण् राममनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व और विचारों की जगह नेताजी सुभाषचंद्र बोस ए ज्योतिबा फुले और जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय को शामिल किया गया। नेताजी और ज्योतिबा फुले के बारे में भी पढ़ाया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन डॉण् लोहिया और जेपी :जिनवे नाम पर विश्वविद्यालय बनादू की कीमत परए दीनदयाल उपाध्याय आश्चर्यजनक तो यह है कि बिहार में शिक्षामंत्री नीतीश कुमार कंपार्टी के ही विजय कुमार चौधरी हैं। चौधरी और नीतीश कुमार के आंख तब खुली जब लालू प्रसाद यादव ने ट्रीट कर आरोप लगाय कि संघी मानसिकता की सरकार समाजवादी नेताओं के विचार पाठ्यक्रम से हटा रही है। बिहार सरकार के जगने एवं कडे निर्देश जारी करने के बाद अब पाठ्यक्रम में फिर से सुधार हो रहा है। लेकिन इस बात

को जलवायु परिवर्तन और की तीव्रता साल दर साल बढ़ रही है। मानसन का मिजाज इस कदम बदल रहा है कि जहां मानसून के दौरान महीने के अधिकांश दिन अब सुखे निकल जाते हैं, वहीं कुछेक दिनों में ही इतनी बारिश हो जाती है जिसके लिए लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। दरअसल वर्षा के पैटर्न में अपेक्षित बदलाव नजर आने लगा है कि बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, जो प्रायः भारी तबाही का कारण बनता है।

हाल ही में पॉट्सडैम इस्टीच्यूट फॉर कलाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के एवं अध्ययन में बताया गया है कि भारतीय मानसून की चाल को जलवायु परिवर्तन और ज्यादा गड़बड़ बना रहा है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश ने जो तबाही मचा रखी है, वह वैशिक तापमान वृद्धि का दुष्परिणाम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम के जिस पैटर्न को कभी सबसे स्थिर माना जाता था, उसमें एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्वोत्तर के तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से मानसूनी वर्षा में करीब पांच फीसदी बढ़ोतरी हो रही है। बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में होती बढ़ोतरी को भी जलवायु परिवर्तन से होने जोड़कर देखा जा रहा है।

जाइकर दखा जा रहा ह।
एक समय था, जब गांव हो या शहर, हर कहीं बड़े-बड़े तालाब और गहरे-गहरे कुएं होते थे और पानी अपने आप धीरे-धीरे इनमें समा जाता था, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ता था लेकिन अब विकास की अंधी दौर में तालाबों की जगह ऊँची-ऊँची इमारतों ने ले ली हैं, शहर कंक्रीट टेंजिंगल बन गए हैं, अधिकांश जगहों पर कुओं को मिट्टी डालकर भर दिया गया है। 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के मुताबिक हमारी फितरत कुछ ऐसी हो गई है कि हम मानसून का भरपूर आनंद तो लेना चाहते हैं किन्तु इस मौसम में किसी भी छोटी-बड़ी आपादा के उत्पन्न होने की प्रबल आशंकाओं के बावजूद उससे निपटने की तैयारियां ही नहीं करते। इसीलिए बदलतामंझ और साथ ही प्रकृति के बदले मिजाज के कारण अब प्रतिवर्ष प्रचण्ड गम्भीर के बाद बारिश रूपी राहत को देशभर में बदलते देर नहीं लगते हैं।

की जांच की मांग हो रही है कि ऐसा किया किसनेघ क्या यह शकरामातश शिक्षा मंत्रालय के किसी अफसर की थी या फिर सीधे राजभवन से इसके लिए निर्देश था। बताने की जरूरत नहीं कि भाजपा और संघ परिवार के इस तरह के दबावों के कारण साझा सरकार चलाते हुए भी नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार अभी तक इन दबावों को झेलते और भरसक परे करते रहते हैं। भाजपा के जनसंघ्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी राय भाजपा से अलग है। इसी तरह से पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच कराए जाने की विपक्ष की मांग का समर्थन कर उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर एक तरह का दबाव ही बनाया। उन्होंने जातीय जनगणना पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर इसके लिए उन पर दबाव भी बनाया। प्रधानमंत्री से बातचीत में उन्होंने इसके लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को श्रेय देकर लालू प्रसाद यादव के यहां भी एक खिड़की खुली रखने की कोशिश की। पटेलियम पदार्थी और खासतौर से रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। तो क्या नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मटीरियल होने की बात इस समय भाजपा पर दबाव बनाने के लिए भी कही जा रही है! इसके साथ ही पिछले दिनों जनता दल यू की अंदरूनी कलह भी खुलकर आने लगी थी। नीतीश कुमार के खास रह आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद उनकी जगह सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाल ही में जद यू में शामिल उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नेताओं के अंदरूनी मतभेद सामने आने लगे हैं।

ज्यादा गड़बड़ बना रहा है। मानसून प्रकृति प्रदत्त ऐसा खुशनुमा मौसम है, भीषण गर्मी झेलने के बाद जिसकी बूंदों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह ऐसा मौसम है, जब प्रकृति हमें भरपूर पानी देती है किन्तु पानी की कमी से बूरी तरह जूँझते रहने के बावजूद हम इस पानी सहेजने के कोई कारगर इंतजाम नहीं करते और बारिश का पानी वर्थ बहकर समुद्रों में समा जाता है। हालांकि 'रेन वाटर हार्डिस्टिंग' का शोर तो सालभर बहुत सुनते हैं लेकिन ऐसी योजनाएं सिरे कम ही चढ़ती हैं। इन्हीं नाकारा व्यवस्थाओं के चलते चंद धंटों की बारिश में ही दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बैंगलुरु जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी प्रायः जल-प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हल्की-सी बारिश क्या हई, सड़कों पर पानी भर जाता है, गाड़ियां रेंग-रेंगकर चलने लगती हैं, रेल तथा विमान सेवाएं प्रभावित होती हैं, सड़कें धंस जाती हैं, जगह-जगह जलभराव होने से पैदल चलने वालों का बुरा हाल हो जाता है। यह कोई इसी साल की बात नहीं है बल्कि हर साल यही नजारा सामने आता है लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे पुख्ता इंतजाम कभी नहीं किए जाते, जिससे बारिश के पानी का संचयन किया जा सके और ऐसी समस्याओं से जिज्ञास मिले।

हमारी व्यवस्था का काला सच यही है कि न कहीं कोई जवाबदेह नजर आता है और न ही कहीं कोई जवाबदेही तय करने वाला तंत्र दिखता है। हर प्राकृतिक आपदा के समक्ष उससे बचाव की हमारी समस्त व्यवस्था ताश के पत्तों की भाँति ढह जाती है। ऐसी आपदाओं से बचाव तो दूर की कौड़ी है, हम तो मानसून में सामान्य वर्षा होने पर भी बारिश के पानी की निकासी के मामले में साल दर साल फेल साबित हो रहे हैं। देशभर के लगभग तमाम राज्यों में प्रशासन के पास पर्याप्त बजट के बावजूद प्रतिवर्ष छोटे-बड़े नालों की सफाई का काम मानसून से पहले अधूरा रह जाता है, जिसके चलते ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। अनेक बार ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं, जिनसे पता चलता रहा है कि मानसून की शुरुआत से पहले ही करोड़ों रुपये का घपला करते हुए

